Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की चुनौतियाँ, अवसर एवं प्रतिस्पर्धात्मकता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Abdul Rahman

Assistant Professor
Department of Commerce, Govt. P.G. College, Sambhal, Uttar Pradesh

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) का योगदान रोजगार, उत्पादन, निर्यात, क्षेत्रीय संतुलन, उद्यमिता-विकास और सामाजिक-आर्थिक समावेशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के बाद भारतीय MSME क्षेत्र के समक्ष एक द्वैत परिदृश्य उभरा है—एक ओर वैश्विक बाज़ार, तकनीक, आपूर्ति-श्रृंखला और निर्यात-विस्तार के नए अवसर उपलब्ध हुए; दूसरी ओर तीव्र प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अवरोध, तकनीकी पिछड़ापन, गुणवत्ता-मानकीकरण, विपणन-संकट, अवसंरचनात्मक बाधाएँ और नीतिगत असमानताएँ अधिक स्पष्ट हुईं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय MSMEs की वैश्वीकरण-जनित चुनौतियों, अवसरों एवं प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों, वैचारिक विमर्श, नीतिगत दस्तावेजों तथा 2000 से 2014 के मध्य प्रकाशित साहित्य के आधार पर निर्मित है। अध्ययन में प्रतिस्पर्धात्मकता को केवल लागत या मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी-अनुकूलन, उत्पादकता, गुणवत्ता, नवाचार, बाज़ार-सुगमता, संस्थागत समर्थन और नीति-ढाँचे के समेकित परिणाम के रूप में देखा गया है। शोध-पत्र यह तर्क प्रस्तुत करता है कि भारतीय MSMEs की वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता केवल बाज़ार-उदारीकरण से नहीं, बल्कि सक्षम वित्त, तकनीकी उन्नयन, क्लस्टर-आधारित विकास, कौशल-संवर्धन, डिजिटल एकीकरण, गुणवत्ता-प्रमाणीकरण और नीति-समन्वय पर निर्भर करती है। निष्कर्षतः, वैश्वीकरण MSMEs के लिए न तो केवल संकट है, न ही केवल अवसर; यह एक ऐसी संरचनात्मक परिस्थिति है जिसमें सक्षम संस्थागत हस्तक्षेप के अभाव में अवसर असमान रूप से वितरित होते हैं और चुनौतियाँ तीव्र रूप से अनुभव की जाती हैं। इस प्रकार, भारतीय MSMEs की दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक बहु-आयामी, समावेशी और नवाचारोन्मुख नीति-दृष्टि आवश्यक है।

प्रमुख शब्द: MSMEs, वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता, उदारीकरण, तकनीकी उन्नयन, निर्यात, लघु उद्योग, नीति-विमर्श, भारतीय अर्थव्यवस्था

1. परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास-पथ में लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका बहुआयामी और संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रही है। यह क्षेत्र केवल उत्पादन और रोजगार का स्रोत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन, संसाधनों के विकेंद्रीकृत उपयोग, स्थानीय उद्यमिता के प्रोत्साहन, नवाचार की प्रारंभिक संरचना और सामाजिक-आर्थिक समावेशन का भी आधार है। विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्था में MSMEs को "growth with equity" के व्यावहारिक वाहक के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम पूँजी में अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं और स्थानीय कौशल तथा संसाधनों को आर्थिक मूल्य में रूपांतरित करते हैं (Government of India, 2007; UNIDO, 2002)। 1991 के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने औद्योगिक ढाँचे को गहराई से प्रभावित किया। व्यापार उदारीकरण, आयात शुल्क में कमी, विदेशी निवेश के लिए खुलेपन, औद्योगिक लाइसेंसिंग में शिथिलता और बाज़ार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ने बड़े उद्योगों के साथ-साथ MSMEs की कार्य-स्थितियों को भी मूल रूप से बदल दिया

(Ahluwalia, 2000; Jalan, 2003)। पूर्व-उदारीकरण काल में संरक्षित नीति-पर्यावरण में विकसित हुए छोटे उद्योगों को अब न केवल घरेलू स्तर पर बड़े औद्योगिक समूहों और आयातित उत्पादों से मुकाबला करना पड़ा, बल्कि गुणवत्ता, लागत, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और वितरण के वैश्विक मानकों के अनुसार स्वयं को पुनर्संगठित भी करना पड़ा (Morris et al., 2001; Singh, 2004)। वैश्वीकरण ने भारतीय MSMEs के समक्ष एक जटिल परिस्थिति उत्पन्न की। एक ओर, वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं से जुड़ने, निर्यात बाजार तक पहुँचने, तकनीकी हस्तांतरण, आउटसोर्सिंग, अनुबंध निर्माण तथा उत्पाद विविधीकरण की संभावनाएँ बढ़ीं (OECD, 2004; UNCTAD, 2004)। दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता, सस्ती आयातित वस्तुओं की उपलब्धता, गुणवत्ता-प्रमाणन का दबाव, वित्तीय संस्थानों की कठोरता, अवसंरचनात्मक कमजोरी और नियामक अनुपालन की जटिलताएँ MSMEs की संरचनात्मक सीमाओं को उजागर करने लगीं (SIDBI, 2000; Keshab Das, 2007)। इस प्रकार, वैश्वीकरण का प्रभाव MSMEs पर एकरेखीय नहीं रहा; यह क्षेत्र, उत्पाद, आकार, तकनीकी क्षमता और भौगोलिक स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हुआ।

भारतीय MSME क्षेत्र की विशेषता इसकी विषमता है। इसमें परंपरागत कुटीर उद्योगों से लेकर आधुनिक विनिर्माण इकाइयों और सेवा-आधारित उद्यमों तक विविध संरचनाएँ शामिल हैं। कुछ इकाइयाँ वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में सफलतापूर्वक एकीकृत हुईं, जबकि अनेक इकाइयाँ निम्न उत्पादकता, सीमित तकनीकी क्षमता और असंगठित कार्य-पद्धतियों के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती रहीं (Ramaswamy, 2006; NCAER, 2009)। अतः MSMEs के प्रश्न को केवल "छोटे उद्योगों की समस्या" के रूप में नहीं, बल्कि विकास, औद्योगिक संरचना, संस्थागत अर्थशास्त्र, वैश्विक उत्पादन-प्रणालियों और राष्ट्रीय नीति-क्षमता के अंतर्संबंधों के रूप में समझना आवश्यक है।

परिचय स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने MSME क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए समय-समय पर अनेक नीतिगत पहलें कीं, जिनमें साख-गारंटी, तकनीकी उन्नयन, क्लस्टर विकास, विपणन सहायता, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा MSMED Act, 2006 जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ शामिल हैं (Government of India, 2006; Ministry of MSME, 2011)। इसके बावजूद प्रश्न बना रहा कि क्या ये नीतियाँ वैश्वीकरण की चुनौतियों के समक्ष MSMEs की वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में पर्याप्त रही हैं? क्या MSMEs की समस्याएँ केवल वित्त या तकनीक की हैं, या वे गहरे संस्थागत और संरचनात्मक कारणों से जुड़ी हैं? क्या वैश्वीकरण ने सभी MSMEs को समान अवसर दिए, या केवल अपेक्षाकृत सक्षम उद्यम ही उसका लाभ उठा पाए?

इन्हीं प्रश्नों की पृष्ठभूमि में यह शोध-पत्र भारतीय MSMEs की चुनौतियों, अवसरों और प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन किसी प्राथमिक सर्वेक्षण या प्रत्यक्ष डेटा-संग्रह पर आधारित नहीं है, बल्कि द्वितीयक साहित्य, नीतिगत प्रतिवेदनों, सरकारी दस्तावेजों और 2000–2014 के मध्य उपलब्ध प्रासंगिक अध्ययनों के आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस शोध-पत्र का केंद्रीय तर्क यह है कि वैश्वीकरण के दौर में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रश्न केवल खुले बाजार से नहीं, बल्कि वित्तीय पहुंच, तकनीकी आधुनिकीकरण, कौशल, नवाचार, अवसंरचना, संस्थागत समर्थन और नीति-संगति के परस्पर क्रियाशील ढांचे से जुड़ा है।

2. सैद्धांतिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि

वैश्वीकरण और MSMEs के संबंध को समझने के लिए केवल व्यापार-उदारीकरण के दृष्टिकोण से विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मकता, औद्योगिक संगठन, नवाचार-प्रणाली, संस्थागत अर्थशास्त्र और वैश्विक मूल्य-श्रृंखला जैसे सिद्धांतों का सहारा लेना आवश्यक है।

2.1 प्रतिस्पर्धात्मकता की अवधारणा

प्रतिस्पर्धात्मकता का पारंपरिक अर्थ लागत और मूल्य के आधार पर बाजार में टिके रहने की क्षमता से जोड़ा जाता रहा है। किंतु समकालीन आर्थिक विमर्श में प्रतिस्पर्धात्मकता का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। इसमें उत्पादकता, गुणवत्ता, नवाचार, प्रबंधन-कौशल, प्रौद्योगिकी-अनुकूलन, ब्रांडिंग, आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता और संस्थागत समर्थन

शामिल हैं (Porter, 1990; Lall, 2001)। MSMEs के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मकता का अर्थ केवल कम लागत पर उत्पादन नहीं, बल्कि परिवर्तित मांग, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक बाजार संरचना के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता है।

2.2 वैश्वीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन

वैश्वीकरण को केवल सीमापार व्यापार की वृद्धि के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन, वित्त, तकनीक और सूचना के वैश्विक एकीकरण के रूप में समझना चाहिए। इस प्रक्रिया में घरेलू उद्योगों को विश्वस्तरीय मानकों और प्रतिस्पर्धी दबावों के अनुरूप स्वयं को पुनर्गठित करना पड़ता है। लघु और छोटे उद्यम, जिनके पास संसाधन सीमित होते हैं, इस संरचनात्मक परिवर्तन से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं (Stiglitz, 2002; UNIDO, 2004)। इस संदर्भ में वैश्वीकरण "opportunity-enhancing" और "vulnerability-increasing" दोनों हो सकता है।

2.3 पोर्टर का डायमंड मॉडल

Porter (1990) के अनुसार किसी राष्ट्र या उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता चार प्रमुख तत्वों—कारक स्थितियाँ, मांग स्थितियाँ, संबंधित एवं सहायक उद्योग, तथा फर्म रणनीति/संरचना/प्रतिस्पर्धा—पर निर्भर करती है। MSMEs के संदर्भ में यह मॉडल उपयोगी है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि केवल उद्यम की आंतरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि स्थानीय आपूर्तिकर्ता, प्रशिक्षण संस्थान, बाजार संरचना, क्लस्टर-गतिशीलता और नीतिगत पर्यावरण भी उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।

2.4 संसाधन-आधारित दृष्टिकोण

Resource-Based View के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उन विशिष्ट संसाधनों और क्षमताओं पर आधारित होता है जो मूल्यवान, दुर्लभ, कठिन-अनुकरणीय और संगठनात्मक रूप से उपयोगी हों। MSMEs में यह लाभ अक्सर स्थानीय कौशल, लचीलापन, ग्राहक-उन्मुख उत्पादन, विशिष्ट डिज़ाइन, पारंपरिक ज्ञान, या niche market specialization के रूप में प्रकट हो सकता है। किंतु यदि ये क्षमताएँ तकनीकी उन्नयन और विपणन कौशल से नहीं जुड़तीं, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनका लाभ सीमित रह जाता है।

2.5 वैश्विक मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में प्रतिस्पर्धा अक्सर "firm versus firm" के बजाय "value chain versus value chain" के रूप में होती है। MSMEs यदि वैश्विक मूल्य-श्रृंखला से जुड़ते हैं, तो उन्हें बड़े खरीदारों, निर्यातकों, ब्रांड मालिकों और आपूर्ति नेटवर्क के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। इससे निर्यात और सीखने के अवसर मिलते हैं, किंतु गुणवत्ता, समयबद्धता, लागत-नियंत्रण और प्रमाणन की आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं (Schmitz, 2004; Humphrey and Schmitz, 2002)। भारतीय MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता का महत्वपूर्ण आयाम यही है कि वे मूल्य-श्रृंखला में किस स्तर पर स्थित हैं—केवल कम-मूल्य आपूर्तिकर्ता के रूप में, या उच्च मूल्य-वर्धन करने वाले साझेदार के रूप में।

2.6 संस्थागत अर्थशास्त्र और MSMEs

MSMEs की सफलता केवल बाजार-तर्क से निर्धारित नहीं होती। ऋण उपलब्धता, संपत्ति-अधिकार, संविदा-प्रवर्तन, गुणवत्ता-मानकीकरण संस्थाएँ, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, निर्यात-सहायता, बिजली, सड़क, लॉजिस्टिक्स, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता-समर्थन प्रणालियाँ—ये सभी संस्थागत कारक MSMEs के परिणामों को निर्धारित करते हैं (North, 1990; Sato, 2000)। भारत में MSMEs की चुनौतियों को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि उद्यम-पर्यावरण कितना सक्षम या बाधक है।

3. साहित्य समीक्षा

भारतीय MSMEs पर उपलब्ध साहित्य बहुआयामी है, जिसमें नीतिगत, आर्थिक, तकनीकी, संस्थागत और क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण शामिल हैं। 2000–2014 के मध्य प्रकाशित अध्ययनों में तीन व्यापक प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं: (i) MSMEs

के आर्थिक योगदान और संरचनात्मक महत्व का आकलन, (ii) उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण, तथा (iii) प्रतिस्पर्धात्मकता-वृद्धि हेतु नीति और संस्थागत हस्तक्षेपों का विमर्श।

3.1 MSMEs का आर्थिक महत्व

सरकारी दस्तावेजों और नीति प्रतिवेदनों में MSMEs को रोजगार, उत्पादन और निर्यात का प्रमुख स्रोत माना गया है (Government of India, 2007; Fourth All India Census of MSMEs, 2006-07)। SIDBI (2000) तथा Ministry of SSI के प्रतिवेदनों में भी यह रेखांकित किया गया कि लघु उद्योग क्षेत्र कम पूँजी में उत्पादन और रोजगार उपलब्ध कराने की विशेष क्षमता रखता है। NCAER (2009) ने MSMEs के सामाजिक-आर्थिक महत्व और क्षेत्रीय संतुलन में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

3.2 उदारीकरण का प्रभाव

Ahluwalia (2000) ने उदारीकरण के बाद भारतीय उद्योगों के सामने उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के प्रश्न को केंद्रीय माना। Morris et al. (2001) ने संकेत किया कि लघु उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा का दबाव अधिक तीव्र हुआ है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ तकनीकी मानक तेजी से बदल रहे हैं। Singh (2004) ने यह दर्शाया कि छोटे उद्यमों की समस्याएँ केवल आकार-जनित नहीं हैं, बल्कि संस्थागत समर्थन की कमी और नीति-समन्वय के अभाव से भी जुड़ी हैं।

3.3 वित्तीय चुनौतियाँ

MSMEs के समक्ष ऋण-उपलब्धता की समस्या पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic (2005) ने विकासशील देशों में छोटे उद्यमों के समक्ष वित्तीय अवरोधों को वृद्धि में प्रमुख बाधा माना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में SIDBI, RBI रिपोर्टों और Keshab Das (2007) ने यह बताया कि बैंकिंग प्रणाली में संपार्श्विक-आधारित ऋण-प्रक्रिया, सूचना-असमता और जोखिम-धारणा के कारण MSMEs को पर्याप्त वित्त नहीं मिल पाता। औपचारिक साख तक सीमित पहुँच होने के कारण अनेक इकाइयाँ महँगे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहती हैं।

3.4 तकनीकी पिछड़ापन और नवाचार

Lall (2001) तथा UNIDO (2002, 2004) ने विकासशील देशों के उद्यमों के लिए तकनीकी क्षमता और learning processes को प्रतिस्पर्धात्मकता का केंद्रीय तत्व माना। भारतीय MSMEs के संदर्भ में कई अध्ययनों ने पाया कि तकनीकी उन्नयन की कमी, पुराने मशीनरी, अनुसंधान एवं विकास में न्यून निवेश, और आधुनिक गुणवत्ता प्रणालियों का अभाव उनकी उत्पादकता को सीमित करता है (CII, 2005; Government of India, 2007)। Ramaswamy (2006) ने दर्शाया कि केवल सस्ती श्रम-शक्ति पर आधारित प्रतिस्पर्धा दीर्घकालिक नहीं है; MSMEs को तकनीकी दक्षता और डिजाइन क्षमताओं में निवेश करना होगा।

3.5 क्लस्टर और सामूहिक दक्षता

Schmitz (1995; 2004) ने industrial clustering और collective efficiency की अवधारणा के माध्यम से दिखाया कि छोटे उद्यम एक दूसरे के निकट रहकर आपूर्तिकर्ता, श्रम-बाजार, सूचना और विशिष्ट सेवाओं के साझा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में UNIDO cluster development programme तथा कई क्षेत्रीय अध्ययनों ने दिखाया कि मोरादाबाद, तिरुपुर, राजकोट, लुधियाना, सूरत, फरीदाबाद आदि क्लस्टरों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों के मिश्रण से उत्पादकता और बाज़ार-अनुकूलन की क्षमता विकसित हुई (Nadvi, 1999; CII, 2005)। तथापि सभी क्लस्टर समान रूप से सफल नहीं रहे; संस्थागत समर्थन, अवसंरचना और निर्यात-संयोजन की उपलब्धता के अनुसार परिणाम भिन्न रहे।

3.6 गुणवत्ता, मानकीकरण और निर्यात

वैश्विक बाजारों में प्रवेश के लिए गुणवत्ता-प्रमाणन, स्वच्छता मानक, तकनीकी मानक और समय पर आपूर्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। Humphrey and Schmitz (2002) ने वैश्विक मूल्य-श्रृंखला में छोटे उद्यमों पर "upgrading pressure" का उल्लेख किया। भारतीय MSMEs के संदर्भ में अध्ययनों ने दिखाया कि ISO प्रमाणन, testing facilities, packaging, branding और export intelligence की कमी के कारण अनेक इकाइयाँ निर्यात अवसरों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पातीं (EXIM Bank, 2002; Ministry of MSME, 2011)।

3.7 नीतिगत ढांचा

MSMED Act, 2006 को इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत विकास माना गया, क्योंकि इसने MSMEs की परिभाषा, संवर्धन और विकास हेतु समेकित ढांचा प्रस्तुत किया (Government of India, 2006)। इसके अतिरिक्त credit guarantee, technology upgradation, cluster development, procurement preference और entrepreneurship development जैसी नीतियाँ विकसित की गईं। किंतु साहित्य में यह आलोचना भी मिलती है कि नीति-क्रियान्वयन अक्सर खंडित, नौकरशाहीपूर्ण और सीमित पहुँच वाला रहा (Kumar, 2011; Keshab Das, 2007)।

3.8 शोध-अंतर

उपलब्ध साहित्य में MSMEs की समस्याओं और महत्व पर पर्याप्त चर्चा मिलती है, परंतु एक विश्लेषणात्मक समेकन अपेक्षाकृत कम दिखता है जिसमें वैश्वीकरण को केवल बाहरी दबाव के रूप में नहीं, बल्कि वित्त, तकनीक, विपणन, संस्थान और नीति के अंतर्संबंधों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाली बहुस्तरीय प्रक्रिया के रूप में समझा जाए। इसी शोध-अंतर को यह अध्ययन संबोधित करता है।

4. शोध-अंतर, उद्देश्य एवं परिकल्पनात्मक प्रतिपादन

4.1 शोध-अंतर

पूर्ववर्ती अध्ययन प्रायः MSMEs की समस्याओं को पृथक-पृथक विषयों—जैसे वित्त, तकनीक, निर्यात या क्लस्टर—में विश्लेषित करते हैं। परंतु वैश्वीकरण की परिस्थिति में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता एक समेकित परिणाम है, जिस पर अनेक संरचनात्मक कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थिति में केवल वर्णनात्मक चर्चा पर्याप्त नहीं; एक समेकित विश्लेषण की आवश्यकता है।

4.2 उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय MSMEs की संरचनात्मक और आर्थिक भूमिका का विश्लेषण करना।
2. वैश्वीकरण के संदर्भ में MSMEs के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की पहचान और विश्लेषण करना।
3. वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों का परीक्षण करना।
4. MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण करना।
5. नीतिगत ढांचे की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

4.3 परिकल्पनात्मक प्रतिपादन

यद्यपि यह अध्ययन अनुभवजन्य परीक्षण नहीं करता, तथापि इसके विश्लेषण का मार्गदर्शन निम्न प्रतिपादनों से होता है:

- वैश्वीकरण ने भारतीय MSMEs के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों को बढ़ाया है, परंतु लाभ मुख्यतः उन इकाइयों को मिला जिनकी आंतरिक एवं संस्थागत क्षमताएँ अपेक्षाकृत मजबूत थीं।
- MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रमुख निर्धारक केवल कम लागत नहीं, बल्कि तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता, वित्तीय पहुंच और बाजार-संयोजन का संयुक्त प्रभाव है।
- नीति-समर्थन की प्रभावशीलता MSMEs की विविधता और स्थानीय संस्थागत क्षमताओं पर निर्भर करती है।

5. शोध-पद्धति

यह शोध-पत्र विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें कोई प्राथमिक डेटा-संग्रह, प्रश्नावली, साक्षात्कार या क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अध्ययन के स्रोतों में निम्न शामिल हैं:

- भारत सरकार, MSME मंत्रालय, योजना आयोग, RBI, SIDBI, EXIM Bank और अन्य संस्थागत प्रतिवेदन;
- 2000–2014 के बीच प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तकें और नीति-अध्ययन;
- UNIDO, OECD, UNCTAD, World Bank आदि संस्थाओं की रिपोर्टें;
- MSMEs, वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता, क्लस्टर, वित्त और तकनीकी उन्नयन से संबंधित अकादमिक साहित्य।

पद्धतिगत रूप से यह अध्ययन वर्णनात्मक होने के बजाय विश्लेषणात्मक-व्याख्यात्मक है। इसमें सामग्री-विश्लेषण, तुलनात्मक विवेचन, अवधारणात्मक समेकन और नीतिगत आलोचना की विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य सांख्यिकीय परीक्षण करना नहीं, बल्कि विद्यमान साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट करना है कि वैश्वीकरण किस प्रकार MSMEs की संरचना, चुनौतियों, अवसरों और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है।

6. भारतीय MSMEs का संरचनात्मक एवं प्रवृत्तिगत विश्लेषण

भारतीय MSMEs की संरचना अत्यंत विषम और बहुस्तरीय है। इसमें विनिर्माण, सेवा, पारंपरिक उद्योग, आधुनिक सूक्ष्म-इकाइयाँ, पारिवारिक उद्यम, निर्यातोन्मुख इकाइयाँ और स्थानीय बाजार पर आधारित प्रतिष्ठान शामिल हैं। MSMEs का यह व्यापक दायरा भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक लचीला आधार प्रदान करता है।

6.1 आर्थिक योगदान

MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और निर्यात के बड़े स्रोत के रूप में उभरे हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से श्रम-प्रधान है और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। छोटे उद्यमों के माध्यम से सीमित पूँजी और स्थानीय कौशल का उपयोग कर उत्पादन-संरचना का विकेंद्रीकरण संभव होता है। यही कारण है कि नीति-निर्माता इसे inclusive growth का प्रमुख साधन मानते रहे हैं (Government of India, 2007; NCAER, 2009)।

6.2 क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक महत्व

MSMEs की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये बड़े महानगरों तक सीमित न रहकर छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैले होते हैं। इससे औद्योगिकीकरण का विकेंद्रीकरण होता है और क्षेत्रीय असमानताएँ कुछ हद तक कम होती हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ, अल्पसंख्यक और प्रथम-पीढ़ी के उद्यमियों को भी इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिलते हैं।

6.3 संरचनात्मक कमजोरियाँ

यद्यपि संख्या और रोजगार की दृष्टि से यह क्षेत्र व्यापक है, परंतु इसकी बड़ी संख्या सूक्ष्म और अनौपचारिक इकाइयों की है। इनके पास पूँजी सीमित होती है, औपचारिक लेखांकन नहीं होता, तकनीकी दक्षता कम होती है, और बाजार पहुँच स्थानीय स्तर तक सीमित रहती है। इसलिए पूरे MSME क्षेत्र को एक समान मानना विश्लेषणात्मक रूप से भ्रामक हो सकता है। प्रतिस्पर्धात्मकता और अवसरों का स्तर विभिन्न उप-समूहों में भिन्न-भिन्न है।

6.4 पूर्व-उदारीकरण से पश्च-उदारीकरण तक

पूर्व-उदारीकरण काल में लघु उद्योगों को आरक्षण, संरक्षण और प्रोत्साहन की नीति के अंतर्गत देखा जाता था। उदारीकरण के बाद धीरे-धीरे यह दृष्टिकोण बदलकर प्रतिस्पर्धात्मकता, दक्षता, गुणवत्ता और निर्यात-संभावना की ओर स्थानांतरित हुआ। इससे छोटे उद्योगों को संरक्षित इकाई के बजाय प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाई के रूप में देखने का विमर्श विकसित हुआ।

7. वैश्वीकरण के संदर्भ में चुनौतियाँ

वैश्वीकरण ने MSMEs के लिए अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न कीं, जो केवल बाजार प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं हैं। ये चुनौतियाँ वित्तीय, तकनीकी, विपणन, संस्थागत और नीतिगत स्तरों पर कार्य करती हैं।

7.1 वित्तीय बाधाएँ

MSMEs की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत समस्या वित्त की है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली अक्सर संपार्श्विक, क्रेडिट हिस्ट्री, बैलेंस शीट और जोखिम-मूल्यांकन के मानकों पर MSMEs को कम अनुकूल मानती है। छोटे उद्यमों की सूचना-पारदर्शिता सीमित होने से ऋणदाता जोखिम को अधिक आंकते हैं। परिणामस्वरूप, कार्यशील पूँजी, प्रौद्योगिकी उन्नयन ऋण, निर्यात वित्त और विस्तार ऋण तक पहुंच बाधित होती है (Beck et al., 2005; SIDBI, 2000)। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के लिए उद्यमों को बेहतर मशीनरी, प्रमाणन, डिज़ाइन, पैकेजिंग और विपणन में निवेश करना पड़ता है। यदि वित्त उपलब्ध न हो, तो वे अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते।

7.2 तकनीकी पिछड़ापन

कई भारतीय MSMEs पुराने उपकरणों, कम उत्पादक प्रक्रियाओं और सीमित स्वचालन पर निर्भर रहते हैं। तकनीकी उन्नयन न होने से उत्पादन लागत, गुणवत्ता-संगति, ऊर्जा दक्षता और समयबद्ध आपूर्ति प्रभावित होती है। वैश्विक बाजारों में जहाँ गुणवत्ता और reliability अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ तकनीकी पिछड़ापन प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करता है (Lall, 2001; UNIDO, 2004)।
साथ ही, अनुसंधान एवं विकास में निवेश की क्षमता सीमित होने से MSMEs नवाचार के बजाय अनुकरण पर अधिक निर्भर रहते हैं। इससे वे उच्च-मूल्य उत्पाद श्रेणियों में प्रवेश करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

7.3 गुणवत्ता-मानक और प्रमाणन

वैश्विक व्यापार में तकनीकी मानकों, sanitary and phytosanitary norms, environmental compliance, labor standards तथा certification requirements की भूमिका बढ़ी है। MSMEs के लिए ISO certification, testing, traceability, documentation और process control जैसी व्यवस्थाएँ अपनाना महँगा और जटिल हो सकता है। इस कारण वे उन बाजारों में प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ गैर-शुल्कीय अवरोध महत्वपूर्ण हैं (EXIM Bank, 2002; Humphrey and Schmitz, 2002)।

7.4 विपणन और ब्रांडिंग संबंधी चुनौतियाँ

MSMEs का एक बड़ा वर्ग उत्पाद निर्माण तो कर लेता है, परंतु बाजार-खोज, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वितरण, ग्राहक-अनुसंधान और डिजिटल/आधुनिक विपणन में पीछे रह जाता है। वैश्वीकरण के बाद बाजार केवल स्थानीय मंडी या पारंपरिक व्यापारिक चैनलों तक सीमित नहीं रहा। किंतु MSMEs के पास अक्सर ऐसी संस्थागत क्षमता नहीं होती कि वे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निर्यात एजेंसियों या आधुनिक retail chains तक प्रभावी पहुँच बना सकें।

7.5 आयात प्रतिस्पर्धा

व्यापार उदारीकरण के बाद आयातित वस्तुओं, विशेषकर कम कीमत और बड़े पैमाने पर उत्पादित माल, ने घरेलू छोटे उद्यमों पर दबाव बढ़ाया। वे इकाइयाँ जो संरक्षित बाजार के लिए कार्य कर रही थीं और जिनकी उत्पादकता/गुणवत्ता सीमित थी, उन्हें सबसे अधिक आघात पहुँचा। सस्ते आयातों के कारण कई उप-क्षेत्रों में घरेलू MSMEs का बाजार-साझा घटा या उन्हें उत्पाद-विविधीकरण के लिए बाध्य होना पड़ा।

7.6 अवसंरचनात्मक बाधाएँ

बिजली की अनियमित आपूर्ति, खराब परिवहन, उच्च लॉजिस्टिक लागत, सीमित भंडारण, परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी और औद्योगिक सेवाओं का अभाव MSMEs की दक्षता कम करता है। बड़े उद्यम जहाँ इन समस्याओं को संसाधनों के बल पर कुछ हद तक प्रबंधित कर लेते हैं, वहीं छोटे उद्यम इनसे अधिक प्रभावित होते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में समय पर आपूर्ति और मानक-आधारित उत्पादन के लिए अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7.7 सूचना एवं बाजार बुद्धिमत्ता की कमी

वैश्विक बाजार में अवसरों का लाभ उठाने के लिए मूल्य-सूचना, खरीदारों की पसंद, प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियाँ, नियामक परिवर्तनों, व्यापार समझौतों और तकनीकी रुझानों की जानकारी आवश्यक है। MSMEs सूचना-संग्रह और विश्लेषण में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। परिणामस्वरूप वे strategic response विकसित नहीं कर पाते।

7.8 कौशल और मानव संसाधन

तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता-प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित श्रम और प्रबंधकीय दक्षता की आवश्यकता होती है। MSMEs में औपचारिक प्रशिक्षण कम होने से उत्पादन प्रबंधन, lean systems, quality control, export documentation और supply chain management जैसी क्षमताएँ सीमित रह जाती हैं।

7.9 संस्थागत और नीतिगत जटिलताएँ

यद्यपि MSMEs के लिए अनेक योजनाएँ हैं, परंतु उनकी जानकारी, पहुँच, आवेदन-प्रक्रिया, अनुमोदन, निगरानी और कार्यान्वयन में जटिलता रहती है। कई उद्यम नीति-सहायता का लाभ केवल इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रियाएँ जटिल और समय-साध्य होती हैं। इससे नीति का intended benefit जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाता।

8. अवसरों का विश्लेषण

वैश्वीकरण को केवल चुनौतियों की दृष्टि से देखना अधूरा होगा। भारतीय MSMEs के लिए इसने अनेक अवसर भी उत्पन्न किए, जिनका लाभ कुछ क्षेत्रों और उद्यमों ने सफलतापूर्वक उठाया।

8.1 वैश्विक बाजार तक पहुँच

उदारीकरण के बाद निर्यात बाजारों तक पहुँच की संभावनाएँ बढ़ीं। विशेषकर वस्त्र, परिधान, चमड़ा, इंजीनियरिंग goods, ऑटो-components, gems and jewellery, हस्तशिल्प और कुछ food processing segments में MSMEs ने बाहरी मांग का लाभ उठाया। निर्यात-उन्मुख इकाइयों को बड़े बाजार, विदेशी मुद्रा अर्जन और उत्पादकता-अनुशासन के लाभ प्राप्त हुए।

8.2 आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े घरेलू उद्योगों द्वारा outsourcing और vendor development के विस्तार ने MSMEs के लिए आपूर्ति-श्रृंखला में प्रवेश के अवसर खोले। इससे उन्हें स्थिर मांग, गुणवत्ता-उन्नयन और प्रौद्योगिकीय सीखने का अवसर मिला। ऑटो-components, light engineering और electronics assembly जैसे क्षेत्रों में यह विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुआ।

8.3 तकनीकी सीख और उन्नयन

वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दबाव केवल संकट नहीं, बल्कि सीखने का अवसर भी है। जिन उद्यमों ने नई मशीनरी अपनाई, प्रक्रिया-सुधार किए, गुणवत्ता-प्रणालियाँ लागू कीं और डिज़ाइन/उत्पाद-विकास पर ध्यान दिया, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ। क्लस्टर कार्यक्रमों और buyer-supplier relationships के माध्यम से तकनीकी सीखने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

8.4 विशिष्ट बाजारों में विशेषज्ञता

छोटे उद्यमों की लचीलापन और ग्राहक-विशिष्ट उत्पादन क्षमता उन्हें niche markets में लाभ दे सकती है। हस्तशिल्प, डिज़ाइन-आधारित उत्पाद, customized engineering components, specialty textiles, organic products और traditional knowledge-based products जैसे क्षेत्रों में MSMEs अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। वैश्वीकरण के दौर में बाजारों का segmentation बढ़ा है, जिससे ऐसी विशेषज्ञता का महत्व बढ़ा है।

8.5 क्लस्टर-आधारित प्रतिस्पर्धात्मकता

जहाँ MSME क्लस्टर विकसित हुए, वहाँ साझा आपूर्तिकर्ता, प्रशिक्षण, मशीनरी सेवाएँ, बाजार-सूचना, परीक्षण सुविधाएँ और संयुक्त ब्रांडिंग की संभावनाएँ बढ़ीं। क्लस्टर छोटे उद्यमों को पैमाने की अर्थव्यवस्था का विकल्प प्रदान करते हैं। सामूहिक दक्षता (collective efficiency) वैश्वीकरण की लागतों को कम कर सकती है।

8.6 सेवा क्षेत्र में विस्तार

MSMEs की चर्चा अक्सर विनिर्माण तक सीमित रहती है, जबकि वैश्वीकरण के दौर में सेवा-आधारित MSMEs—आईटी समर्थित सेवाएँ, मरम्मत, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स, प्रोफेशनल सपोर्ट, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य-संबंधी सेवाएँ—भी तेज़ी से उभरीं। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पूँजी के साथ नवाचार और बाजार-विस्तार की संभावनाएँ अधिक हैं।

8.7 उद्यमिता और स्थानीय नवाचार

वैश्विक exposure ने स्थानीय उद्यमियों को नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और व्यापार मॉडल्स के प्रति प्रेरित किया। कई MSMEs ने विदेशी तकनीकों का स्थानीय अनुकूलन, डिज़ाइन परिवर्तन, लागत-कुशल इंजीनियरिंग और frugal innovation के माध्यम से अपनी जगह बनाई। भारत जैसे देश में जहां लागत-संवेदनशील बाजार और विविध मांग मौजूद है, वहाँ MSMEs स्थानीय नवाचार के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं।

9. प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण

MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रश्न इस शोध-पत्र का केंद्रीय विषय है। इसे समझने के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता को अनेक आयामों के संयोजन के रूप में देखें।

9.1 लागत बनाम उत्पादकता

भारतीय MSMEs को अक्सर सस्ती श्रम-शक्ति के आधार पर प्रतिस्पर्धी माना जाता है, परंतु केवल निम्न मजदूरी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं देती। यदि उत्पादन प्रक्रिया अल्प-दक्ष, ऊर्जा-अक्षम और अपव्यय-प्रधान है, तो वास्तविक लागत-लाभ सीमित हो जाता है। इसलिए लागत प्रतिस्पर्धा की तुलना में उत्पादकता-आधारित प्रतिस्पर्धा अधिक टिकाऊ है।

9.2 तकनीकी क्षमता

तकनीकी क्षमता में केवल मशीनरी ही नहीं, बल्कि process know-how, maintenance practices, quality systems, product development और problem-solving ability शामिल हैं। MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता उन स्थितियों में अधिक होती है जहाँ वे तकनीक को आत्मसात कर उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करते हैं।

9.3 गुणवत्ता और विश्वसनीयता

वैश्विक और आधुनिक घरेलू बाजार में buyer confidence अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता की निरंतरता, समय पर आपूर्ति, traceability और दस्तावेज़ीकरण से MSMEs की बाज़ार-विश्वसनीयता बनती है। यदि उद्यम अनियमित गुणवत्ता या विलंबित आपूर्ति से ग्रस्त है, तो प्रतिस्पर्धा में बने रहना कठिन हो जाता है।

9.4 नवाचार और डिजाइन

प्रतिस्पर्धात्मकता केवल existing products को सस्ते में बेचने की क्षमता नहीं है; यह नए उत्पाद, बेहतर डिजाइन, ग्राहक-विशिष्ट समाधान और process innovation से भी जुड़ी है। MSMEs में incremental innovation की पर्याप्त संभावना होती है, परंतु इसके लिए डिजाइन संस्थाओं, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्योग-संस्थान सहयोग और बाजार feedback तंत्र की आवश्यकता होती है।

9.5 बाजार-संयोजन और ब्रांडिंग

उत्पादन क्षमता तब तक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में परिवर्तित नहीं होती जब तक बाजार तक पहुँच, visibility और ग्राहक-संपर्क की क्षमता विकसित न हो। MSMEs जो केवल intermediaries पर निर्भर रहते हैं, वे मूल्य-श्रृंखला में निम्न हिस्से पर बने रहते हैं। ब्रांडिंग, direct marketing और export networking उन्हें उच्च मूल्य-वर्धन की ओर ले जा सकते हैं।

9.6 संस्थागत समर्थन

क्रेडिट, परीक्षण प्रयोगशाला, तकनीकी परामर्श, skill development, export facilitation, legal compliance support और cluster associations जैसे संस्थागत तंत्र MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। जहाँ यह पारितंत्र मजबूत है, वहाँ छोटे उद्यम अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

9.7 क्लस्टर और नेटवर्क

अकेला MSME वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सीमित हो सकता है, लेकिन networked MSMEs अधिक सक्षम होते हैं। क्लस्टर-आधारित सहयोग, subcontracting, common facility centres, shared branding और joint procurement जैसी व्यवस्थाएँ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती हैं। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहाँ scale economy बड़े उद्योगों को लाभ देती है।

9.8 औपचारिकता और प्रबंधन दक्षता

MSMEs की बड़ी संख्या अनौपचारिक संचालन-पद्धति पर आधारित होती है। इससे वे बैंक ऋण, निर्यात-सहायता, कानूनी संरक्षण और गुणवत्ता प्रणालियों के लाभ से वंचित रह सकते हैं। बेहतर लेखांकन, inventory management, cost control और HR practices प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करते हैं।

10. नीतिगत विमर्श

भारतीय MSMEs के लिए नीतिगत समर्थन का उद्देश्य लंबे समय तक संरक्षण और प्रोत्साहन रहा, किंतु वैश्वीकरण के बाद यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हुआ कि क्या नीति केवल survival support दे रही है या competitiveness enhancement भी कर रही है।

10.1 MSMED Act, 2006 का महत्व

यह अधिनियम MSMEs की परिभाषा, विकास और संवर्धन के लिए संस्थागत ढांचे को स्पष्ट करता है। इसने विनिर्माण के साथ सेवा क्षेत्र को भी औपचारिक रूप से शामिल कर नीति-क्षेत्र का विस्तार किया। भुगतान विलंब, प्रोत्साहन, पंजीकरण और संस्थागत समन्वय के लिए भी इसका महत्व है। तथापि अधिनियम का प्रभाव क्रियान्वयन क्षमता पर निर्भर रहा।

10.2 ऋण और साख-गारंटी

MSMEs के लिए credit guarantee schemes, priority sector lending और specialized financial institutions महत्वपूर्ण रहे हैं। परंतु इनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंकिंग प्रणाली MSMEs को केवल जोखिमपूर्ण श्रेणी के रूप में देखती है या विकास-समर्थक दृष्टिकोण अपनाती है। सूचना-आधारित क्रेडिट स्कोरिंग,

cash-flow based lending और fintech integration जैसी व्यवस्थाएँ आगे उपयोगी हो सकती हैं, यद्यपि 2000–2014 के साहित्य में इनका प्रारंभिक संकेत ही मिलता है।

10.3 तकनीकी उन्नयन समर्थन

Technology Upgradation Fund, common facility centres, tool rooms, design clinics, quality improvement programmes और testing infrastructure MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। केवल मशीनरी खरीद पर सब्सिडी पर्याप्त नहीं; तकनीक के उपयोग, रखरखाव और process integration पर भी ध्यान देना होगा।

10.4 क्लस्टर विकास कार्यक्रम

क्लस्टर विकास MSMEs के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी नीति उपकरण माना गया है। इससे संयुक्त अवसंरचना, बाजार-सूचना, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और नवाचार-साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। परंतु क्लस्टर नीति तभी सफल होती है जब स्थानीय संघ, नेतृत्व, trust और संस्थागत समन्वय मौजूद हो।

10.5 विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन

ट्रेड फेयर, buyer-seller meets, export facilitation cells, e-marketing support, packaging assistance और branding support MSMEs को वैश्विक बाजार से जोड़ सकते हैं। भारतीय नीति ढांचे में विपणन सहायता मौजूद रही है, किंतु व्यापक स्तर पर इसकी पहुँच सीमित रही। अधिक integrated market development framework की आवश्यकता है।

10.6 कौशल और उद्यमिता विकास

प्रतिस्पर्धात्मकता का आधार केवल पूँजी और मशीनरी नहीं, बल्कि मानव संसाधन भी है। technical training, managerial education, entrepreneurship development और shop-floor skill formation के लिए MSMEs को संस्थागत सहायता की आवश्यकता है। ITIs, polytechnics, engineering institutions और industry associations के साथ साझेदारी उपयोगी हो सकती है।

10.7 नियामक सरलता

MSMEs पर अनुपालन-भार अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है, क्योंकि सीमित प्रशासनिक क्षमता के बावजूद उन्हें अनेक लाइसेंस, कर, रजिस्ट्रेशन और श्रम/पर्यावरण मानकों का पालन करना पड़ता है। regulatory simplification, single-window systems और digital processing उनके transaction costs कम कर सकते हैं।

11. आलोचनात्मक विमर्श

MSMEs पर बहस में अक्सर दो अतिवादी दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, कि छोटे उद्यम स्वाभाविक रूप से रोजगार-सृजन और समावेश के वाहक हैं, इसलिए उन्हें निरंतर संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा, कि बाजार प्रतिस्पर्धा स्वयं अक्षम इकाइयों को बाहर कर देगी और केवल दक्ष उद्यम बचेंगे। दोनों दृष्टिकोण अधूरे हैं। पहला दृष्टिकोण इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि संरक्षण यदि तकनीकी, प्रबंधकीय और बाजार उन्नयन से न जुड़ा हो तो वह स्थायी निर्भरता पैदा कर सकता है। दूसरा दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि सभी उद्यम समान प्रारंभिक शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि वास्तव में MSMEs संरचनात्मक असमानताओं, वित्तीय बहिष्करण और अवसंरचनात्मक कमियों से घिरे रहते हैं। अतः उचित नीति-दृष्टि “protective insulation” और “pure market exposure” के बीच संतुलन स्थापित करने वाली होनी चाहिए—अर्थात ऐसी व्यवस्था जो उद्यमों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे, न कि केवल अस्थायी राहत दे। इसी प्रकार, वैश्वीकरण की आलोचना भी संतुलित होनी चाहिए। यह सही है कि उदारीकरण ने कई कमजोर इकाइयों को संकट में डाला, परंतु यह भी उतना ही सही है कि कुछ क्षेत्रों में इसी प्रक्रिया ने निर्यात, गुणवत्ता-उन्नयन और तकनीकी सीखने के नए रास्ते खोले। इसलिए MSMEs की विफलता या सफलता को केवल वैश्वीकरण के पक्ष/विपक्ष

के सरल द्विभाजन में नहीं समझा जा सकता। मूल प्रश्न यह है कि क्या भारतीय संस्थागत ढांचा MSMEs को वैश्विक अवसरों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर पाया?

12. निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय MSMEs वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद बहुस्तरीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह क्षेत्र रोजगार, उत्पादन, निर्यात, उद्यमिता, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समावेशन का प्रमुख आधार है, लेकिन इसकी बड़ी संख्या वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधकीय और विपणन सीमाओं से घिरी हुई है। वैश्वीकरण ने इनके लिए बाजार-विस्तार, निर्यात, तकनीकी सीख, आउटसोर्सिंग और विशेषीकृत उत्पादन के अवसर उपलब्ध कराए हैं; परंतु इन अवसरों का लाभ सभी इकाइयों तक समान रूप से नहीं पहुँचा। तुलनात्मक रूप से वे उद्यम और क्लस्टर अधिक सफल रहे जिनके पास तकनीकी क्षमता, संस्थागत सहयोग, बाजार-संपर्क और गुणवत्ता-प्रणालियों को अपनाने की क्षमता थी। यह निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण है कि MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को केवल लागत-आधारित दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पादकता, गुणवत्ता, समयबद्धता, नवाचार, बाजार-संयोजन, वित्तीय पहुंच और संस्थागत समर्थन के संयोजन से निर्मित होती है। यदि MSMEs के पास आधुनिक मशीनरी हो पर बाजार न हो, या बाजार हो पर कार्यशील पूँजी न हो, या वित्त हो पर गुणवत्ता-मानक न हों, तो वे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा में स्थिर नहीं रह सकते।
अतः नीति के स्तर पर निम्न सुझाव विशेष महत्व रखते हैं:

1. वित्तीय समावेशन का गहनकरण

MSMEs के लिए cash-flow based lending, collateral-free credit expansion, credit guarantee strengthening, receivables financing और export credit की सुगमता बढ़ाई जानी चाहिए।

2. तकनीकी उन्नयन को समग्र रूप में देखना

तकनीकी सहायता केवल मशीन खरीद तक सीमित न रहकर process improvement, energy efficiency, design support, testing, maintenance और digital integration को भी शामिल करे।

3. क्लस्टर-आधारित विकास को प्राथमिकता

common facility centres, design labs, testing labs, shared logistics, skill centres और branding support के माध्यम से MSME clusters की सामूहिक दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए।

4. गुणवत्ता और प्रमाणन सहायता

ISO, HACCP, CE markings, testing compliance और export standards के लिए subsidized support, advisory services और simplified certification access विकसित किया जाए।

5. विपणन एवं ब्रांडिंग समर्थन

MSMEs को domestic and international market intelligence, e-commerce readiness, trade fair participation, packaging innovation और brand development में संस्थागत सहायता मिले।

6. कौशल, प्रबंधन और उद्यमिता

तकनीकी कौशल के साथ-साथ cost management, inventory control, digital tools, export documentation और strategic planning का प्रशिक्षण भी दिया जाए।

7. नीति-समन्वय और कार्यान्वयन सुधार

केंद्र, राज्य, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग संघों और तकनीकी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हो। योजनाओं को fragmented mode में चलाने के बजाय integrated MSME competitiveness framework विकसित किया जाए।

8. सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए विभेदित नीति

MSMEs एक समरूप श्रेणी नहीं हैं। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों की चुनौतियाँ भिन्न हैं; अतः size-sensitive policies आवश्यक हैं।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण भारतीय MSMEs के लिए न तो केवल हानिकारक सिद्ध हुआ है और न ही स्वतः लाभकारी। इसका प्रभाव उद्यमों की आंतरिक क्षमता, क्षेत्रीय पारितंत्र, संस्थागत समर्थन और नीति-व्यवस्था की गुणवत्ता पर निर्भर रहा है। यदि भारत को MSME क्षेत्र को वास्तविक अर्थों में प्रतिस्पर्धी बनाना है, तो उसे संरक्षणवादी मानसिकता से आगे बढ़कर क्षमता-निर्माण, नवाचार, समेकित समर्थन और बाजार-उन्मुख संस्थागत विकास की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे।

संदर्भ सूची

1. Ahluwalia, I. J. (2000). Economic performance of states in post-reforms period. *Economic and Political Weekly*, *35*(19), 1637–1648.
2. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter? *Journal of Finance*, *60*(1), 137–177.
3. CII. (2005). *SMEs and competitiveness in India*. Confederation of Indian Industry.
4. EXIM Bank. (2002). *Export potential of small and medium enterprises in India*. Export-Import Bank of India.
5. Government of India. (2006). *Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006*. Ministry of Law and Justice.
6. Government of India. (2007). *Fourth all India census of micro, small and medium enterprises, 2006–07*. Ministry of MSME.
7. Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? *Regional Studies*, *36*(9), 1017–1027.
8. Jalan, B. (2003). *India's economic crisis and the way ahead*. Oxford University Press.
9. Keshab Das. (2007). *SMEs in India: Issues and possibilities in times of globalization* (Working Paper). Institute for Human Development.
10. Kumar, A. (2011). Small and medium enterprises in India: Policy issues and support mechanisms. *Journal of Entrepreneurship and Development*, *6*(2), 45–62.
11. Lall, S. (2001). *Competitiveness, technology and skills*. Edward Elgar.
12. Ministry of MSME. (2011). *Annual report 2010–11*. Government of India.
13. Morris, S., Basant, R., Das, K., Ramachandran, K., & Koshy, A. (2001). *The growth and transformation of small firms in India*. Oxford University Press.
14. Nadvi, K. (1999). Collective efficiency and collective failure: The response of the Sialkot surgical instrument cluster to global quality pressures. *World Development*, *27*(9), 1605–1626.
15. NCAER. (2009). *Contribution of the unorganized and small enterprise sector to the economy*. National Council of Applied Economic Research.
16. North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
17. OECD. (2004). *Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy*.
18. Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
19. Ramaswamy, K. V. (2006). *Small and medium enterprises in India in the era of globalization* (IEG Working Paper). Institute of Economic Growth.
20. Sato, Y. (2000). How do small firms in East Asia develop? The role of local and regional factors. *Developing Economies*, *38*(3), 338–362.
21. Schmitz, H. (1995). Collective efficiency: Growth path for small-scale industry. *Journal of Development Studies*, *31*(4), 529–566.
22. Schmitz, H. (2004). *Local enterprises in the global economy: Issues of governance and upgrading*. Edward Elgar.
23. SIDBI. (2000). *Report on small scale industries sector*. Small Industries Development Bank of India.

24. Singh, M. K. (2004). *Globalization and small scale industries in India: Opportunities and challenges*. Deep & Deep Publications.
25. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton.
26. UNCTAD. (2004). *Trade and development report*. United Nations.
27. UNIDO. (2002). *Competing through innovation and learning: Industrial development report*.
28. UNIDO. (2004). *SMEs and industrial competitiveness*. United Nations Industrial Development Organization.
29. World Bank. (2008). *World development report: Agriculture for development*.